MR. SPEAKER: Not allowed. Without my permission nothing will go on record.

*(Interruptions)***

12.22 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

(i) NEED FOR SURVEY TEAM TO STUDY SOIL EROSION BY RIVERS IN HIMACHAL PRADESH.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का एक ऐसा प्रान्त है जहां बहुत वर्षा होती है और यहां बहुत से नदी नालों का संचालन होता है। मैं भारत सरकार का ध्यान इस क्षेत्र के जमीन के कटाव की ओर दिलाना चाहता हूं और इस कारण से गरीब किसानों की हजारों एकड़ जमीन कटाव हो जाने की वजह से बर्बाद हो गयी है। यही नहीं, जो चाराएं व घासनियां जिससे इस क्षेत्र के लोगों के पशु पालन का काम होता है, वह भूमि भी अधिक मात्रा में खराब हो जाने के कारण बर्बाद हो गई है, जिनको यहां के किसान सुधार करने के काबिल नहीं रहे । कई परिवार तो इस प्रकार के हैं जिनके पास अगर 100 बीघा भूमि थी, वह सब की सब कटाव में बर्बाद हो गई और अब वह अपने आपको लाचार पाते हैं । इस सब कटाव को रोके जाने के लिए एक ही उपाय है कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की इन बड़ी-बड़ी नदियों और नालों की तरफ ध्यान देकर एक सर्वेक्षण दल को राज्य सरकार में भेजे और वहां के नदी नालों का सर्वे करे और किसानों के नुक्सान का अन्दाजा करके भारत सरकार को दे और इस सम्बन्ध में योजना मंत्री हिमाचल सरकार को उतनी राशि देने का प्रबन्ध करें जो इन नदी नालों के पानी को ठीक किया जा सके और यहां के किसानों के जमीन के कटाव को रोका जा सके।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि किसानों के नुक्सान, जो काटाव की वजह से हुआ है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार तुरन्त कार्यवाही करे और जिला सिरमौर में जमुना नदी, मारकंडा, रनाट नदी और इसके साथ ही नदी नालों को तुरन्त ठीक किया जाय और इसी प्रकार जिला सोलन में सरसा नदी और गिरी नदी, अश्नी नदी, ऊना में सोवा नदी, चम्बा में रावी, मण्डी में व्यास नदी, इन नदियों के बहाव को रोकने हेतु अगर तुरन्त कदम नहीं उठाए गये तो हिमाचल प्रदेश की उन पहाड़ियों को, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी है, खराब होने का भय है।

अतः मैं भारत सरकार से आशा रखता हूं कि हिमाचल सरकार इस सम्बन्ध में उस समय तक पूरी मदद नहीं कर सकती जब तक भारत सरकार राज्य सरकार को अनुदान के रूप में करोड़ों रुपयों का प्रावधान नहीं करती । इसलिये इस गम्भीर समस्या को सामने रखते हुए राज्य सरकार को अधिक धन देने का प्रावधान किया जाए ।

(ii) NEED FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO SMALL SCALE UNITS BY NATIONALISED BANKS.

श्री भीखाभाई (बासवड़ा): अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों का महत्व समझते हुए ही हमारी 1956 की औद्योगिक नीति में इनकी स्थापना एवं प्रादुर्भाव की समुचित व्यवस्था की गई थी । तदनन्तर और भी कई योजनायें इस सदर्भ में बनाई गई । हाल ही में बनाई गई ऐसी ही एक योजना है "जिला औद्योगिक केन्द्र" योजना । इसके तहत इन उद्योगों को एक ही छत के नीचे वित्त, तकनीकी सहायता आदि आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

इन्हीं योजनाओं से प्रेरित हो कर बहुत से लोगों ने, जिसमें शिक्षित नवयुवक भी शामिल हैं, ऐसे छोटे उद्योग लगाने का फैसला किया। इनमें एक उद्योग फरीदाबाद में घड़ी बनाने के कारखाने का था। खेद का विषय है कि यद्यपि यह उद्योग तकनीकी रूपेण सक्षम घोषित किया गया, तथापि इसके लिए वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाई । यह उद्योग बैंक बड़ौदा की एक स्थानीय शाखा के पास गया । बजाये इसके कि वहां से इस उद्योग को धन प्राप्त होता, उलटा

**Not recorded.

बैंक ने इसका कोई 10,000 रुपया बेकार में खर्च कराया । इसी तरह का एक और उदाहरण कलकत्ते का है । वहां की आंध्र बैंक चौरंगी बांच के पास यह उद्योग एक शिक्षित बेरोजगार द्वारा कार्बन फिल्म रिपिस्टर बनाने के लिए गया । बैंक ने न ही कोई वित्त की व्यवस्था की और न ही इस बारे में पार्टी का जवाब दिया । ऐसे और उदाहरण मेरे पास हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट है, तो फिर ये संस्थाएं क्यों नहीं सरकारी नीतियों को अमल में लाती हैं । क्या चन्द व्यक्ति इस तरह से निहित स्वार्थ की वजह से सरकार की नीतियों को निरर्थक बना सकते हैं ?

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SOME HON. MEMBERS: Sir, yesterday you created history.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You, as opposition, did your duty and I, as Deputy Speaker did my duty.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Assessments differ.

(iii) NEED FOR MAKING AVAILABLE CHILDREN'S LITERATURE AT CHEAP PRICE.

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बाल साहित्य का देश में अत्यन्त ही अभाव है । जो थोड़ा बहुत उपलब्ध है, वह भी बहुत ही महंगा है । देश का गरीब मजदूर, कृषक और आदिवासी का बच्चा जो कुछ प्रतिशत स्कूल में पढ़ने जाता है, वह भी इन महंगी पुस्तकों को खरीद कर नहीं पढ़ सकता । अतः स्वस्थ मनोरंजन तथा स्वस्थ साहित्य के अभाव में बच्चों में मानसिक शून्यता तथा भटकाव की स्थिति रहती है । अतः केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से मैं निवेदन करूंगी कि देश की ऐतिहासिक धरोहर, महापुरुषों, देश-प्रेमियों, देश विदेश की भौगोलिक तथा आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास की जानकारी चित्रमय कथाओं के माध्यम से देने के लिये ऐसी पुस्तकें निःशुल्क या बहुत ही सस्ती दर पर बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए । सोवियत रूस में बहुत ही सस्ती निःशुल्क ऐसी पुस्तकें बच्चों को दी जाती हैं। क्यों नहीं हमारे देश में नन्हें बच्चों के ज्ञान-वर्द्धन तथा स्वस्थ मनोरंजन के लिए सस्ता, बढ़िया बाल साहित्य हम चित्रमय प्रस्तुत करें । शिक्षा मंत्रालय शिक्षा में बाल साहित्य के लिए भी विशेष मद रखें जिससे बच्चों को सस्ती दर पर बाल साहित्य उपलब्ध कराया जा सके ।

(iv) DELAY IN CONSTRUCTION OF BANSPANI-JAKHPURA RAILWAY-LINE.

**SHRI HARIHAR SOREN (Keonjhar): Mr. Deputy-Speaker. Sir, the inordinate delay in the construction of Jakhpura-Banspani Railway line has adverse impact on the economy of Orissa. The total length of this proposed line is 179 Km. and it has been divided into three phases. The first phase of this line from Jakhpura to Daitari is only 33 km. The construction of the first phase has been completed and already opened for traffic. But it is unfortunate that the construction of second phase from Daitari to Keonjhargarh has not started so far though funds have already been allocated for this 95 km. distance.

Keonjhar district is mainly a mineral rich district and iron ore, manganese and other minerals accumulated in large quantities at different mines can be transported by rail to Paradip for export if this rail line is constructed. The economic development of the State mainly depends on this railway line. Government of India can earn foreign exchange by exporting high grade ores from this mineral belt.

In view of this, I demand that the construction of second phase rail link of Jakhpura-Banspani line should be expedited. The construction of third phase of the railway line from Keonjhargarh to Banspani should be included in the Sixth Plan.

(v) BOMBAY SUBURBAN RAILWAY SERVICE.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Sir, the pressure on the Bombay Suburban Rail Transport has been

**The original speech was delivered in Oriya.